



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032020-216583
CG-DL-E-06032020-216583

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 911]
No. 911]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2020/फाल्गुन 16, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2020/PHALGUNA 16, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2020

का.आ. 1015(अ).—केंद्रीय सरकार, परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड राज्यों में विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले परिसीमन आयोग का गठन करती है, अर्थात् :—

(i) न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई	— अध्यक्ष
(ii) श्री सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त	— सदस्य (पदेन)
(iii) संविधान के, यथास्थिति, अनुच्छेद 243ठ के खंड (1) या अनुच्छेद 243ठ के खंड (1) के अधीन नियुक्त संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के राज्य निर्वाचन आयुक्त	— सदस्य (पदेन)

2. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की नियुक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगी।

3. उक्त परिसीमन आयोग,—

- (i) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के भाग 5 के उपबंधों और परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अनुसार जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों का ;
- (ii) असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अनुसार, परिसीमन करेगा ।

[फा. सं. एच-11019/3/2019-वि.II]

डॉ. जी. नारायण राजू, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th March, 2020

S.O. 1015(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), the Central Government hereby constitutes the Delimitation Commission for the purpose of delimitation of Assembly and Parliamentary constituencies in the Union territory of Jammu and Kashmir and the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland, consisting of the following members, namely:—

- | | | |
|-------|---|---------------------------------|
| (i) | Justice (Retd.) Ranjana Prakash Desai | - Chairperson |
| (ii) | Shri Sushil Chandra,
Election Commissioner | - Member, (<i>ex officio</i>) |
| (iii) | The State Election Commissioner of the concerned State or Union Territory appointed under clause (1) of article 243K or under clause (1) of article 243L of the Constitution, as the case may be. | - Member, (<i>ex officio</i>) |

2. The appointment of Justice (Retd.) Ranjana Prakash Desai shall be for a period of one year from the date of the publication of this notification in the Official Gazette or till further orders, whichever is earlier.

3. The said Delimitation Commission shall delimit the constituencies,—

- (i) of the Union territory of Jammu and Kashmir in accordance with the provisions of part V of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) and the provisions of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002);
- (ii) of the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland in accordance with the provisions of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002).

[F. No. H-11019/3/2019-Leg.II]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.